

# हिन्दुस्तान एकता

वर्ष: 071 अंक: 081 पृष्ठ: 04 | मूल्य: ₹1.00

कैथल, शनिवार 25 अप्रैल, 2026

RNI-HRHIN/26/A1127



## आपकी आवाज हमारी ताकत

आप कोई सामाजिक, धार्मिक आयोजन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी संस्था से जुड़ी कोई खबर, खुला नाला है, पानी से भरा गड्ढा है, रोड टूटी या गड्ढे हैं, हादसे का खतरा है इत्यादि खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो अब दूर नहीं। आपको केवल खबर और खबर से जुड़े बुनियाद दो फोटो कैप्शन के साथ भेजना होगा। आपकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

**ऐसे भेजें**  
वॉट्सअप कर सकते हैं  
**9499422208**  
हमें QR स्कैन कर वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं



## न्यूज ब्रीफ

### मंडियों की व्यवस्थाओं पर डीसी सख्त

कैथल >> शहर की अनाज मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर उठे मुद्दों पर डीसी अपराजिता ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सौजन्य के दौरान किसानों और मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध करवाई जाएं। समाचार पत्रों में अव्यवस्थाओं संबंधी खबर प्रकाशित होने पर डीसी ने मार्केट कमिटी सचिव से जवाब तलब किया। सचिव ने बताया कि पुरानी अनाज मंडी में 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहते हैं और 22 अप्रैल को रात को भी स्टाफ मौजूद था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से की जा सकती है। कूड़ा उठान को लेकर बताया कि मंडी के बीच स्थित होने के कारण बड़े वाहन अंदर नहीं पहुंच पाते, इसलिए कचरे को अस्थायी रूप से एकत्र किया गया है। ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नई मंडी के बाहर का क्षेत्र गगर परिषद के अधीन बताया गया, जबकि परिसर में स्ट्रीट लाइट सुचारु हैं।

### एनसीसी गर्ल्स बटालियन में 'ए' सर्टिफिकेट वितरित, 100% रिजल्ट



लुधियाना। लुधियाना स्थित 3 पंजाब गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा एक औपचारिक समारोह में जूनियर विंग (जेडव्यू) के डेटस को एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इस परीक्षा में के डेटस का परिणाम 100% रहा, जो उनकी मेहनत और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दर्शाता है। इस अवसर पर 21 से 24 अप्रैल तक एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षकों को एनसीसी जेडव्यू पाठ्यक्रम में हुए बदलावों से अवगत कराना और उनके प्रशिक्षण कौशल को मजबूत करना था। सत्र में साहब सुखा, अमिनशमन, स्वास्थ एवं स्वच्छता, जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना था, जिससे डेटस को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। 3 पंजाब गर्ल्स बटालियन एनसीसी को कर्मांडिंग ऑफिसर कर्नल आर.एस. चौहान ने डेटस और प्रशिक्षकों के प्रदर्शन की सराहना की और उनके समर्पण व उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया।

## सख्त रुख >> लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी, जन शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश

# समाधान शिविर में ढेर से पहुंचे अधिकारियों पर डीसी सख्त

हिन्दुस्तान एकता >> कैथल

लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में वीरवार को डीसी अपराजिता का सख्त रुख देखने को मिला। शिविर में देरी से पहुंचे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर उपस्थित होकर आमजन की समस्याओं का समाधान करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में देरी या लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि प्रत्येक फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुनकर निष्पक्ष समझना है उसका प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी



स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। शिविर में लावारिस कुत्तों की समस्या और अवैध अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। स्थानीय लोगों ने खतरनाक कुत्तों के कारण बड़ रही

दुर्घटनाओं पर चिंता जताई, वहीं सुंदरान मोहल्ला में दुकानों के अतिक्रमण से रास्ता बाधित होने की शिकायत दी गई। डीसी ने डीएससी कपिल कुमार को दोनों मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा वार्ड 22 की दर्शना देवी ने विधवा पेंशन बंद होने की शिकायत रखी,

जिस पर डीसी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल कार्रवाई कर पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जरीर टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रहा है और बुनियादी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

रुख नहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। शिविर में लावारिस कुत्तों की समस्या और अवैध अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। स्थानीय लोगों ने खतरनाक कुत्तों के कारण बड़ रही

# हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर

>> 5 लाख तक ऋण व 7% ब्याज अनुदान से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

कलासो देवी >> कैथल

डीसी अपराजिता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके तहत महिलाएं डेयरी, छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र और स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न कार्य शुरू कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन सेवाओं के अंतर्गत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, श्री-व्हीलर और टैक्सि, जबकि सेवा क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक,



फोटोस्टेड, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस, आचार-पापड़ निर्माण, बिस्कुट व आइसक्रीम यूनिट जैसे कार्य शामिल हैं। इस योजना के तहत समय पर ऋण की किस्त चुकाने पर तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी।

### योजना के लिए पात्रता नियम

योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी आवश्यक है। आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह किसी बैंक ऋण को डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।

### आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करवानी होंगी।

### लापता बच्चों के मामलों में पुलिस थानों में पैनाल वकील तैनात

कलासो देवी >> कैथल

सीजेएम कंवल कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में लापता बच्चों से संबंधित मामलों में तुरंत कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न पुलिस थानों में पैनाल अधिवक्ताओं की तैनाती की गई है। यह तैनाती 1 मई से 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगी। यह व्यवस्था बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ एवं अन्य के अनुपालन में लागू की गई है। इसके तहत संबंधित पुलिस स्टेशनों से सूचना प्राप्त होने पर अधिवक्ता लापता बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने बताया कि तैनात पैनाल अधिवक्ताओं में रमेश देवी (तितरम व सोहन थाना), मनीषा (पुंडरी थाना व एसवीबी), मीनाक्षी (सिटी व सदर थाना कैथल), मोनिका (सिविल लाइन व कलायत थाना), निशा (ढांड व राजौद) तथा स्वीटी जीआरपी व महिला थाना शामिल हैं।

# जनगणना 2027 के लिए स्व-गणना की अपील

>> 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरें परिवार का विवरण, पहली बार मिली डिजिटल सुविधा

कैथल। डीसी अपराजिता ने जनगणना 2027 के तहत आमजन से अपील की है कि वे 30 अप्रैल तक स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेकर जनगणना कार्य में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार नागरिकों को स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है। डीसी ने बताया कि नागरिक se.census.gov.in पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित तरीके से अपने परिवार का डाटा दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल 16 अप्रैल से शुरू हो चुका है और निर्धारित अवधि तक सक्रिय रहेगा। फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने पर प्रत्येक परिवार को 11 अंकों की यूनिक स्व-गणना आईडी मिलेगी, जिसे सत्यापन के समय प्रणाली को दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लगभग 33 प्रश्नों के उत्तर देकर 15 से 20 मिनट में पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे घर-घर जाकर होने वाली पूछताछ में भी आसानी होगी। डीसी ने कहा कि यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें कर्मा मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करेंगे। जो लोग ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, उनके लिए पारंपरिक व्यवस्था भी जारी रहेगी।



से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरें परिवार का विवरण, पहली बार मिली डिजिटल सुविधा

### स्व-गणना से जुड़े मुख्य बिन्दु...

- » अंतिम तिथि: 30 अप्रैल
- » पोर्टल: se.census.gov.in
- » प्रक्रिया समय: 15-20 मिनट
- » कुल प्रश्न: लगभग 33
- » यूनिक आईडी: 11 अंकों की
- » सुविधा: पहली बार स्व-गणना का विकल्प
- » विकल्प: ऑनलाइन व घर-घर दोनों तरीके उपलब्ध

में पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे घर-घर जाकर होने वाली पूछताछ में भी आसानी होगी। डीसी ने कहा कि यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें कर्मा मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करेंगे। जो लोग ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, उनके लिए पारंपरिक व्यवस्था भी जारी रहेगी।

# मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन 5 मई को, आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ी

हिन्दुस्तान एकता >> कैथल

डीसी अपराजिता ने बताया कि हरियाणा सरकार की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र स्थित तख सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। इच्छुक श्रद्धालु सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क होगी, जिसमें रहने, खाने और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी शामिल होंगी। डीसी ने बताया कि लाभार्थियों का चयन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने पात्र बुजुर्गों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

**मध्य तीर्थों के दिव्य दर्शन कराएंगी हरियाणा सरकार**

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से नि:शुल्क होगा तीर्थ दर्शन

- ₹1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार होंगे लाभान्वित
- 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग कर सकेंगे नि:शुल्क तीर्थ दर्शन

उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालु लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में भी अपनी जानकारी दे दें, ताकि यात्रा की व्यवस्थाएं सुचारु रूप से की जा सकें।

# एनएचआरसी की 12वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता 2026 शुरू, 30 जून तक भेज सकते हैं एंट्री

कलासो देवी >> कैथल

डीसी अपराजिता ने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 12वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि जिले के युवा, विद्यार्थी एवं आम नागरिक इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतिभागी अपनी लघु फिल्में 30 जून 2026 तक Google Drive के माध्यम से nhreshortfilm@gmail.com पर भेज सकते हैं। डीसी ने बताया कि देश का कोई भी नागरिक, किसी भी आयु वर्ग से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। फिल्म हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में बनाई जा सकती है, जबकि गैर-अंग्रेजी फिल्मों के लिए अंग्रेजी सब-टाइटल अनिवार्य होंगे। फिल्म की अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेताओं को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी और दिशा-निर्देश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रतियोगिता से जुड़ी खास जानकारी

- » आयोजन: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- » भागीदारी: सभी आयु वर्ग के नागरिक
- » फिल्म अवधि: 3 से 10 मिनट
- » भाषा: हिंदी/अंग्रेजी/अन्य भारतीय भाषा (अंग्रेजी सबटाइटल अनिवार्य)
- » अंतिम तिथि: 30 जून 2026
- » भेजने का माध्यम: Google Drive (nhreshortfilm@gmail.com)

पुरस्कार

- » प्रथम: 2 लाख
- » द्वितीय: 1.5 लाख
- » तृतीय: 1 लाख
- » विशेष उल्लेख: 50-50 हजार (अधिकतम 4 प्रतिभागी)

## सुविचार

हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी।

## संपादकीय

## AI का बढ़ता प्रभाव: अवसर या चुनौती?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आज के दौर की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक बन चुकी है। यह केवल मशीनों को "स्मार्ट" बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे सोचने, काम करने और निर्णय लेने के तरीकों को भी तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में यह प्रश्न बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि एआई हमारे लिए अवसर है या चुनौती? AI के सकारात्मक पहलुओं पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि इसने कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI आधारित तकनीक रोगों की जल्दी पहचान करने में मदद कर रही है, जिससे इलाज अधिक प्रभावी हो पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में परसॅनलाइज्ड लर्निंग के माध्यम से छात्रों को उनकी क्षमता और जरूरत के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। कृषि में भी एआई मौसम की भविष्यवाणी और फसल प्रबंधन में किसानों की मदद कर रहा है। उद्योगों में ऑटोमेशन के जरिए उत्पादन तेज और सटीक हुआ है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। इसके साथ ही AI ने नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए करियर विकल्प खुल रहे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस दौर में AI नवाचार (इन्वेंशन) को बढ़ावा दे रहा है, जिससे देश की प्रगति को भी गति मिल रही है।

हालांकि, AI के बढ़ते प्रभाव के साथ कई गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है। ऑटोमेशन के कारण कई पारंपरिक नौकरियां खत्म होने के कारगर पर हैं, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। एआई सिस्टम बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करते हैं, जिससे उसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

एक और महत्वपूर्ण चिंता यह है कि कहीं AI पर अत्यधिक निर्भरता मानव की रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को कमजोर न कर दे। मशीनें भले ही तेज और सटीक हों, लेकिन उनमें मानवीय संवेदनशीलता और नैतिक समझ नहीं होती। ऐसे में केवल तकनीक पर भरोसा करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है।

दरअसल, AI अपने आप में तो पूरी तरह अवसर है और न ही पूरी तरह चुनौती। यह एक शक्तिशाली साधन है, जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में उपयोग करते हैं। यदि सरकारें और समाज मिलकर इसके लिए स्पष्ट नीतियां, नैतिक मानदंड और उचित नियंत्रण व्यवस्था बनाएं, तो AI मानव जीवन को बेहतर और आसान बना सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि हम AI को केवल तकनीकी नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी समझें। संतुलित उपयोग, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ अपनाया गया AI निश्चित रूप से एक उज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

## जनप्रतिनिधियों की पेंशन पर सवाल...

डॉ. प्रियंका सौरभ लेखिका

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जनता सर्वोच्च मानी जाती है और जनप्रतिनिधि जनता के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। परंतु समय-समय पर कुछ ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, जो इस मूल भावना पर प्रश्नचिह्न खड़े कर देते हैं। पूर्व सांसदों की पेंशन और सुविधाओं को लेकर उठी हालिया बहस भी इसी श्रेणी में आती है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और सुविधाओं का औचित्य क्या है, तो इसने देशभर में एक नई चर्चा को जन्म दिया। यह प्रश्न केवल एक प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है। आखिर क्यों एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि अन्य वर्गों को कड़े नियमों और सीमाओं में बांध दिया जाए? यह सवाल आम नागरिक के मन में स्वाभाविक रूप से उठता है।

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं ताकि वे उनके हितों की रक्षा कर सकें और समाज के विकास के लिए काम करें। यह एक जिम्मेदारी है, कोई स्थायी लाभ प्राप्त करने का माध्यम नहीं। परंतु जब जनप्रतिनिधियों को आजीवन पेंशन, कई प्रकार की सुविधाएं और विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह व्यवस्था सेवा की भावना को बढ़ावा देती है या इसे एक विशेषाधिकार में बदल देती है? एक सामान्य सरकारी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए वर्षों तक सेवा करनी पड़ती है। कई बार 20 से 30 वर्षों की नौकरी के बाद ही वह इस सुविधा का हकदार बनता है। इसके विपरीत, सांसद बनने के लिए केवल एक कार्यकाल—जो कि पाँच वर्षों का होता है—भी पर्याप्त है। यह असमानता न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है।

भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत पर आधारित है। हर नागरिक को समान अवसर और समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन एक विशेष वर्ग को अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं, तो यह सिद्धांत कमजोर पड़ता दिखाई देता है। पूर्व सांसदों की पेंशन का मुद्दा इसी असमानता का प्रतीक बन गया है। जब देश का एक बड़ा वर्ग आर्थिक संघर्ष से जूझ रहा हो, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से परेशान हो, तब ऐसे विशेषाधिकार जनता के बीच असंतोष पैदा करते हैं। यह असंतोष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी होता है।

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन पेंशनों और सुविधाओं का खर्च अंततः जनता के करों से ही पूरा होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह संसाधनों का सही उपयोग है? क्या यह धन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में निवेश नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि कुल बजट में यह खर्च बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मुद्दा केवल राशि का नहीं, बल्कि सिद्धांत का है। यदि एक व्यवस्था असमानता को बढ़ावा देती है, तो उसे केवल इसलिए सही नहीं ठहराया जा सकता कि उसका आर्थिक प्रभाव सीमित है।

इस विषय पर एक पक्ष यह भी है कि जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल के बाद कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि सांसद बनने के बाद व्यक्ति को अपने पेशे, व्यवसाय या नौकरी से दूरी बनानी पड़ती है। ऐसे में कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके पास स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि यदि जनप्रतिनिधियों को आर्थिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तो वे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। वे बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

(यह लेखिका के निजी विचार हैं)

संदीप तोमर  
डी2/1 जीवन पार्क उत्तम नगर, नई दिल्ली



हर वर्ष जैसे ही बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते हैं, समाज में एक अजीब-सी हलचल शुरू हो जाती है। कहीं मिठाइयां बंटती हैं, तो कहीं घरों में सननाटा पसरता होता है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा दबाव जिस पर होता है, वह है—बच्चा। यह सवाल अब गंभीरता से पूछा जाना चाहिए कि क्या वास्तव में बच्चों का यह तनाव उनकी अपनी क्षमता का परिणाम है, या फिर हमारी—यानी अभिभावकों की—खराब परेंटिंग का असर?

आज के समय में यह एक कटु सत्य बन चुका है कि बच्चे अंक (मार्क्स) को लेकर तनाव में जीते हैं। कई बार यह तनाव इतना गहरा हो जाता है कि वे आत्महत्या जैसे भयावह कदम उठा लेते हैं। यह

स्थिति किसी एक बच्चे या परिवार की नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक मानसिकता की देन है। हमने अनजाने में परीक्षा और अंकों को जीवन का अंतिम सत्य बना दिया है।

व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालना पूरी तरह से टाला जा सकता है। मैंने कभी अपनी बेटियों से परीक्षा देकर आने के बाद उनका प्रश्नपत्र नहीं देखा, न यह पूछा कि कौन-सा उत्तर कैसा लिखा। न ही परिणाम को लेकर कोई जिज्ञासा जताई। मेरा मानना है कि बच्चा जो लिखकर आ चुका है, वह अब बदला नहीं जा सकता। फिर उस पर चर्चा करके उसे क्यों मानसिक तनाव दिया जाए? क्या वह चर्चा केवल हमारे 'जानने' के लिए होती है, या वास्तव में बच्चे के भले के लिए?

दरअसल, समस्या केवल बच्चों में नहीं, अभिभावकों की सोच में भी है। हम अपने बच्चों की उपलब्धियों को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं। एक पड़ोसी की बेटी का उदाहरण सामने है—जब मैंने

परिणाम जानने के लिए संपर्क किया, तो जवाब मिला कि "देख लिया है" उस एक वाक्य में एक संकोच, एक छुपापना, और कहीं न कहीं एक सामाजिक भय छिपा था—कि कहीं परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप न हुआ हो, और लोग क्या सोचेंगे। यह प्रवृत्ति बताती है कि परीक्षा परिणाम अब केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक स्टेटस का प्रतीक बन गया है।

यही कारण है कि आज आवश्यकता केवल बच्चों को पढ़ाने की नहीं, बल्कि अभिभावकों को 'पढ़ाने' की है। यह विचार अब अतिशयोक्ति नहीं लगता कि अच्छी परेंटिंग के लिए भी स्कूल या प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। समाजशास्त्र जैसे विषयों में परेंटिंग पर एक अस्थायी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी बेहतर अभिभावक बन सके।

शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था पर भी पुनर्विचार आवश्यक है। आज शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक अंक-केन्द्रित हो गया है, जबकि वास्तविक आवश्यकता व्यवसायोन्मुखी और जीवनोपयोगी शिक्षा की है। क्या

वास्तव में एक परीक्षा यह तय कर सकती है कि कोई बच्चा जीवन में कितना सफल होगा? यदि नहीं, तो फिर ऐसी परीक्षा प्रणाली का औचित्य क्या है, जो छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करे?

जब मैं अपने पुराने शैक्षणिक दस्तावेज देखा तो तो यह प्रश्न मन में आता है कि यदि मेरे अंक और अधिक होते, तो क्या वास्तव में मेरे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाता? शायद नहीं। मैं आज भी वही होता—एक शिक्षक, एक लेखक। यह अनुभव यह समझने के लिए पर्याप्त है कि अंक जीवन का अंतिम सत्य नहीं है।

अतः समय की मांग है कि हम शिक्षा और परेंटिंग—दोनों को नए दृष्टिकोण से देखें। बच्चों को अंक नहीं, आत्मविश्वास दें; तुलना नहीं, समझ दें; और सबसे बढ़कर—उन पर भरोसा करें। क्योंकि एक स्वस्थ और संतुलित बच्चा ही एक स्वस्थ समाज की नींव रख सकता है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

## एक व्यक्ति, अनेक पहचान समाज-व्यवस्था का दर्पण

डॉ. अभिनव, अफिस्टेंट प्रोफेसर, जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, डिप्लोमा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक कमजोर प्रमाण पत्र (सामान्य जाति हेतु), स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, शरद लाइसेंस, संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा पंजीकृत दस्तावेज आदि सम्मिलित हैं।

रेलवे पहचान पत्र, पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के संबंध में सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र, गैस कनेक्शन बिल, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड

पेंशनभोगी फोटो कार्ड, राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा लेटरहेड पर जारी फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड विकलांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, राजपत्र अधिसूचना कानूनी नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र, भूमि राजस्व प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र, किसी देश में व्यक्ति की पहचान बहुत बड़ी मायने रखती है क्योंकि यह नहीं होगी तो कैसे मानव से संबंधित सिस्टम आगे बढ़ेगा? इसलिए आईडेंटिटी सिस्टम को बनाना और बनाये रखना भी चुनौती से कम नहीं है। लेखक समझता है कि भारत को एक आईडेंटिटी सिस्टम अपना चाहिए जिससे पारदर्शिता, समय, धन की कटौती होगी।

रूसी सिस्टम-प्रणाली में कई घटक शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय पहचान संख्या (एसएनआईएन), रूसी सरकार इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की ओर जा रही है जो पारंपरिक कागज दस्तावेजों की जगह लेगी। इस डिजिटलीकरण का उद्देश्य व्यक्तिगत पहचान और डेटा प्रबंधन की दक्षता में सुधार करना है। चीनी रजिडेंट आई कार्ड, जिसे रजिडेंट आईडेंटिटी कार्ड पिनाइन भी कहा जाता है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में व्यक्तिगत पहचान के लिए एक आधिकारिक पहचान दस्तावेज है। 1 अक्टूबर, 1999 से, पीआरसी की स्टेट कार्डसिल ने नागरिक पहचान संख्या प्रणाली को स्थानापी को मंजूरी दी, और वर्तमान में इसमें 18 अंकों का एक कोड होता है। इस संख्या का कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर के समान है। प्रत्येक नागरिक के पास एक अद्वितीय संख्या होती है जो उसके पूरे जीवनकाल में अपरिवर्तित रहती है, और केवल इस संख्या को जानकर ही आप धारक की जन्म तिथि, जन्म स्थान और लिंग के बारे में पता लगा सकते हैं। चाइना के महाशक्ति की ओर बढ़ते कदम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका समझी जा सकती है। इसी तरह पाकिस्तान में राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (नादरा) द्वारा 120 मिलियन से अधिक कम्प्यूटरकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जो अपनी आईडेंटिटी दस्तावेज सेवाओं का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है।

भारत में व्यक्ति के स्वयं के आईडेंटिटी के लिए कुछ आईडेंटिटी सिस्टम बनाया है जिसमें नेशनल आईडेंटिटी और राज्यों में स्टेट योजनाओं के तहत भी आईडेंटिटी सिस्टम बनाया है। इस आईडेंटिटी सिस्टम के संदर्भ में थोड़ा और आगे बढ़ें तो व्यक्ति के तौर पर और पहचान मिलती है—सर्वजनिक जीवन बीमा निगमों एवं कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य

पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, डिप्लोमा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक कमजोर प्रमाण पत्र (सामान्य जाति हेतु), स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, शरद लाइसेंस, संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा पंजीकृत दस्तावेज आदि सम्मिलित हैं। रेलवे पहचान पत्र, पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के संबंध में सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र, गैस कनेक्शन बिल, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड पेंशनभोगी फोटो कार्ड, राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा लेटरहेड पर जारी फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड विकलांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, राजपत्र अधिसूचना कानूनी नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र, भूमि राजस्व प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र, किसी देश में व्यक्ति की पहचान बहुत बड़ी मायने रखती है क्योंकि यह नहीं होगी तो कैसे मानव से संबंधित सिस्टम आगे बढ़ेगा? इसलिए आईडेंटिटी सिस्टम को बनाना और बनाये रखना भी चुनौती से कम नहीं है। लेखक समझता है कि भारत को एक आईडेंटिटी सिस्टम अपना चाहिए जिससे पारदर्शिता, समय, धन की कटौती होगी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

## नारी शक्ति... न्याय के बीच झूलता लोकतांत्रिक संतुलन

डॉ. अशोक कुमार रंगा, राजनेता एवं समाजसेवी

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के सिद्धांत में निहित है। यही वह आधार है जो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान महत्व प्रदान करता है। किंतु जब व्यवहारिक व्यवस्था इस सिद्धांत से भटकने लगे, तब लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है। आज महिला आरक्षण, जनगणना, परिसीमन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर जो बहस चल रही है, वह केवल एक विधेयक का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की समग्र संरचना और उसके संतुलन का प्रश्न बन चुकी है।

महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक (13 वीं संविधान संशोधन) एक ऐतिहासिक अवसर था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देना था। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत है, जो देश की आधी आबादी के अनुपात में अत्यंत कम है। प्रस्ताव यह था कि लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 816 किया जाए और इनमें से लगभग 33 प्रतिशत, यानी लगभग 269 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। यह परिवर्तन न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण होता।

यदि यह विधेयक पारित हो जाता, तो 2029 के आम चुनावों में ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत तक पहुंच सकता था। लेकिन संसद में यह विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका। परिणामस्वरूप महिलाओं को मिलने वाला यह अंधकार फिलहाल टल गया और अब इसके 2034 तक खिचकने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

यह विषय केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। संसदीय सीटों की संख्या बढ़ने का सीधा लाभ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को भी मिलना था। वर्तमान में इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सीमित है, क्योंकि कुल सीटों की संख्या 543 पर स्थिर है। यदि सीटों की संख्या 816 तक बढ़ती, तो उसी अनुपात में एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में भी वृद्धि होती। इससे इन वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत होता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठता।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने इस असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, ताकि इन वर्गों को समान अवसर मिल सके। संसद और विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक आवश्यक साधन है। ऐसे में सीटों की संख्या

बढ़ने से इन वर्गों को मिलने वाला अतिरिक्त प्रतिनिधित्व एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता था। लेकिन महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के पारित न होने से यह पूरा लाभ भी फिलहाल टल गया है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या इस निर्णय से इन वर्गों की अपेक्षाओं को भी आघात नहीं पहुंचा है?

इस पूरे विषय को समझने के लिए वर्तमान संसदीय संरचना की असमानता को देखना आवश्यक है। आज लोकसभा की 543 सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हैं। पिछले पांच दशकों में देश की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिनिधित्व का ढांचा उसी अनुपात में अद्यतन नहीं हुआ। इसका परिणाम यह है कि आज संसदीय क्षेत्रों के बीच मतदाताओं की संख्या में भारी असंतुलन देखने को मिलता है।

देश में लगभग 127 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ 20 लाख से अधिक मतदाता हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के बीच एक सांसद का प्रभाव संवाद स्थापित करना कठिन हो जाता है और जनसमस्याओं का समाधान भी प्रभावित होता है। इसके विपरीत, कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ मतदाताओं की संख्या मात्र 60 हजार तक सीमित है। यह स्थिति लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत को कमजोर करती है, जिसमें हर वोट की समान कीमत होनी चाहिए।

इसी असमानता को दूर करने के लिए परिसीमन आवश्यक है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबे समय तक फ्रीज रखी गई। अब जब यह विषय पुनः चर्चा में है, तो यह केवल सीटों के पुनर्वितरण का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने का प्रयास है। जनगणना इस पूरी प्रक्रिया की आधारशिला है। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो सकी, लेकिन अब 2026 की जनगणना आरम्भ हो चुकी है। यह जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी और दूसरे चरण में जातीय जनगणना भी की जाएगी, जिसका निर्णय कैबिनेट द्वारा 2025 में लिया जा चुका है। वर्तमान में यह प्रक्रिया जारी है, लेकिन ओबीसी वर्ग की महिलाओं की विस्तृत गणना अभी शेष है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन आंकड़ों के आधार पर ही संसद में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। 1951 और 1971 की जनगणना के दौरान जातीय जनगणना का विरोध हुआ था। 1957 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, जिसे भी तत्काल लागू नहीं किया गया और अंततः 1990 में वी. पी. सिंह सरकार ने इसे लागू किया। यह इतिहास दर्शाता है कि सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे हमेशा समय और सहमति की प्रक्रिया से गुजरते रहे हैं।

यदि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार पहले जनगणना, फिर परिसीमन और उसके बाद आरक्षण लागू किया जाता है, तो यह पूरा चक्र 2030 के बाद ही पूरा होगा। इसका अर्थ है कि महिलाओं के साथ-साथ एससी और एसटी वर्ग को मिलने वाला अतिरिक्त प्रतिनिधित्व भी 2034 तक टल जाएगा।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

## विद्यालय से विश्वविद्यालय तक: पत्रकारिता शिक्षा क्यों है अधूरी?

अनिल कुमार यादव (सहायक प्राध्यापक खेल विश्वविद्यालय हरियाणा, राई 1)

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता को "चौथा स्तंभ" कहा जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि इसकी शिक्षा आज भी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। स्कूल स्तर पर छात्रों को भाषा, लेखन और सामान्य ज्ञान तो सिखाया जाता है, परंतु संवाद, सूचना विश्लेषण, मीडिया साक्षरता और खबरों की समझ जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित रूप से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, जब विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तर पर पत्रकारिता और जनसंचार की

पढ़ाई में प्रवेश करते हैं, तो उनके पास न तो बुनियादी समझ होती है और न ही व्यावहारिक कौशल, जिससे यह शिक्षा अधूरी और असंतुलित प्रतीत होती है।

पत्रकारिता शिक्षा की यह कमी अन्य विषयों से इसके अपर्याप्त समन्वय के कारण भी है। उदाहरण के लिए, राजनीति विज्ञान से जुड़कर पत्रकारिता लोकतंत्र, शासन और नीतियों की गहरी समझ विकसित कर सकती है; समाजशास्त्र के साथ यह सामाजिक संरचना, असमानता और सांस्कृतिक विविधता को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकती है; अर्थशास्त्र से जुड़कर यह आर्थिक नीतियों, बाजार और विकास के मुद्दों को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचा सकती है; वहीं विज्ञान और तकनीक के साथ इसका संबंध विज्ञान संचार, डिजिटल मीडिया और फेक न्यूज की पहचान में अत्यंत उपयोगी हो सकता है। इसके बावजूद, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में

पत्रकारिता को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सीमित कर दिया जाता है, जिससे इसकी व्यापक संभावनाएं सिमट जाती हैं।

आज के डिजिटल युग में, जब सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूचना के प्रमुख स्रोत बन चुके हैं, पत्रकारिता शिक्षा का महत्व अन्य विषयों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है। यह केवल खबर लिखने या रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को जागरूक, तार्किक और जिम्मेदार बनाने का कार्य भी करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता की विद्यालय स्तर से ही एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाए, ताकि छात्रों में प्रारंभ से ही विश्लेषणात्मक सोच, अभिव्यक्ति कौशल और मीडिया की समझ विकसित हो सके। विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, बहुविषयक और तकनीकी रूप से सशक्त

बनाने की आवश्यकता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान देने के बजाय, छात्रों को फील्ड वर्क, इंटरैक्शन, न्यूजरूम अनुभव और डिजिटल टूल्स के प्रयोग पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के साथ पत्रकारिता के समन्वित पाठ्यक्रम लागू किए जानें चाहिए, ताकि विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ प्रभावी संचारक भी बन सकें।

यदि हम एक जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो पत्रकारिता शिक्षा को विद्यालय से विश्वविद्यालय तक एक मजबूत और समग्र ढांचे में विकसित करना होगा। यह केवल एक विषय नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली शक्ति है, जिसे अन्य विषयों से जोड़कर और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)



## नया प्रोजेक्ट

रिश्तेदारों को लेकर कड़ी हैरान करने वाली बात मेधा शंकर को अब नहीं आते शादी के प्रपोजल



मेधा शंकर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में अरंज मैरिज और रिश्तों की कहानी दिखाई जाएगी। इसी सिलसिले में एक इंटरव्यू के दौरान मेधा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच बताया है, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान रह गए हैं। मेधा ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों अब उन्हें शादी के प्रपोजल मिलना बंद हो गए हैं।

कामयाबी के बाद क्यों नहीं आ रहे शादी के रिश्ते? एक इंटरव्यू में मेधा ने बताया कि '12th फेल' हिट होने के बाद और नेशनल क्रश बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। पहले उनके रिश्तेदार अक्सर शादी की बातें करते थे और नए-नए रिश्ते लेकर आते थे। लेकिन अब फेम मिलने के बाद रिश्तेदारों ने रिश्ते लाना बंद कर दिया है। एक्ट्रेस ने कहा 12वीं फेल के बाद मेरी लाइफ में सबकुछ बदल गया। रिश्तेदारों को लगने लगा कि मेरा करियर कहीं न कहीं आगे

बढ़ रहा है। इसलिए अब कोई भी मेरे लिए शादी के रिश्ते नहीं लाता।  
 एक्टिंग को सिर्फ शौक मानते थे रिश्तेदार... मेधा ने कहा, 'पहले वो बार-बार इस बारे में बात करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाऊंगी। उन्हें लगता था कि एक्टिंग सिर्फ मेरा शौक है और चार साल के बाद मैं घर वापस लौट जाऊंगी।  
 पापा का सपोर्ट और शादी पर मेधा की सोच... मेधा के परिवार हमेशा उनके सपोर्ट में रहता है और शादी को लेकर प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। मेधा ने कहा, 'मेरे पापा ने कभी भी शादी को लेकर मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया। मैं इस मामले में खुद को लकी मानती हूँ। हाँ, वो इतना जरूर कहते हैं कि सही समय पर और सही इंसान से शादी कर लेना। वो समझते हैं कि फिलहाल मेरा काम ज्यादा जरूरी है। अभी शादी में वक्त है, लेकिन आगे चलकर मैं शादी जरूर करूंगी।

कभी 10 लोगों संग शेयर किया कमरा, आज लठजरी लाइफ जीते हैं मनोज बाजपेयी

बॉलीवुड के दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी आज अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ प्रेरणादायक जीवन कहानी के लिए भी जाने जाते हैं। बिहार के छोटे से गाँव बेवला से निकलकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका सफर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन आज वे सफलता की ऊँचाइयों पर हैं। मुंबई पहुँचने के बाद मनोज बाजपेयी का जीवन आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में वे एक चॉल में रहते थे, जहाँ उन्हें कई लोगों के साथ कमरा साझा करना पड़ता था। ऑडिशन के दौरान कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक बार उनकी फोटो तक कूड़ेदान में फेंक दी गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।



अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में बनी हुई है। 17 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि गिरते कलेक्शन के बीच भी फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।  
 डे 6 का बॉक्स ऑफिस हाल... रिपोर्टरों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को करीब 6115 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। हालाँकि यह आंकड़ा पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 78190 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। वीकडेज में गिरावट

आना आम बात है, लेकिन फिल्म ने अपनी पकड़ पूरी तरह नहीं छोड़ी है।  
 तुलना और चर्चा में फिल्म... फिल्म की तुलना अन्य हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से भी की जा रही है। खासकर 'भूल भुलैया 3' से मुकाबले में यह थोड़ा पीछे नजर आई। वहीं, वामिका गब्बी की तुलना ऐश्वर्या राय बच्चन से किए जाने पर अक्षय कुमार ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि वामिका की अपनी अलग पहचान है और उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई है।  
 कुल मिलाकर, 'भूत बंगला' भले ही वीकडेज में थोड़ी धीमी पड़ी हो, लेकिन फिल्म की पकड़ अभी भी बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन में फिर उछाल देखने को मिल सकता है।

## अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा हुए मुरीद

पूरी दुनिया में नंबर 1 बनी विजय वर्मा की नई सीरीज 'मटका किंग'

विजय वर्मा की नई वेब सीरीज 'मटका किंग' इस समय हर तरफ छाई हुई है। इस सीरीज में विजय वर्मा की एक्टिंग इतनी दमदार है कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आमिर खान, विक्की कौशल और करण जोहर जैसे बड़े सितारों ने तो पहले ही इस शो को जबरदस्त बताया था, लेकिन अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के 'शहशाह' अमिताभ बच्चन ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का नाम भी जुड़ गया है। आइए आपको बताते हैं कि इन सुपरस्टार्स ने 'मटका किंग' को लेकर क्या कहा है और कैसे इसकी तारीफ की है।  
 अमिताभ बच्चन ने दी शुभकामनाएं... अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया (X हैंडल) पर 'मटका किंग' का ट्रेलर शेयर किया। उन्होंने टीम को बधाई देते हुए लिखा, "मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।"  
 प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार हिरानी भी हुए एक्साइटेट... अमिताभ बच्चन के बाद अब प्रियंका चोपड़ा ने भी 'मटका किंग' की टीम को जीत की बधाई दी है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर शो का पोस्टर शेयर करते हुए पूरी टीम को शाबाशी दी। इतना ही नहीं, मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस शो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेट हैं।  
 दुनिया भर में बज रहा है डंका... विजय वर्मा का यह जादू सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। 'मटका किंग' इस समय भारत और दुबई (UAE) दोनों देशों में नंबर 1 पर चल रही है। सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि पूरी दुनिया की 'टॉप 10' सीरीज की लिस्ट में यह इकलौती भारतीय सीरीज है, जो 8वें नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है।



## क्या है 'मटका किंग' की कहानी?

यह कहानी हमें 1960 के दशक की पुरानी मुंबई में ले जाती है। विजय वर्मा ने इसमें 'बूज भट्टी' नाम के एक चालाक आदमी का रोल किया है जो रूई (कपास) का छोटा सा व्यापार करता है। वह समाज में इज्जत और नाम कमाना चाहता है। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई यह कहानी कैसे पूरे शहर में फैल जाती है और कैसे इसमें ताकत और पैसे का खेल शुरू होता है, यही इस सीरीज में बहुत ही रोमांचक तरीके से दिखाया गया है। इसे मशहूर डायरेक्टर नागराज मंजुले ने बनाया है।

## कपिल शर्मा-रिद्धिमा कपूर की फिल्म

'दादी की शादी' का ट्रेलर रिलीज दिखा कॉमेडी का असली तड़का



कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और एक्ट्रेस नीतू कपूर की मच-अवेटेड फिल्म 'दादी की शादी' का धमाकेदार ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर मस्ती, इमोशन और कॉमेडी का ऐसा तड़का है, जो दर्शकों को लोटपोट करने के लिए तैयार है। मेकर्स ने इस ट्रेलर के जरिए एक ऐसी कहानी पेश की है, जिसमें हंसी के साथ-साथ परिवार का प्यार भी नजर आ रहा है।  
 ट्रेलर में दिखा मस्ती और हंगामे का डोज... ट्रेलर में दिखाया गया है कि नीतू कपूर दादी की उम्र में शादी करना चाहती हैं, जिससे पूरी कहानी और दिलचस्प बन जाती है। अब ट्रेलर को देखकर साफ लग रहा है कि यह एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनर फिल्म होगी। इसमें रोमांस के साथ-साथ जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिल रही है। फिल्म का निर्देशन आशीष आर। मोहन ने किया है। खास बात यह है कि इस फिल्म में नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी और एक्ट्रेस सादिया खतीब भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। पूरी स्टारकास्ट ने फिल्म में अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी है।  
 रिद्धिमा कपूर के लिए क्यों इमोशनल है यह सफर? रिद्धिमा कपूर साहनी इस फिल्म के जरिए

एक नया अनुभव साझा कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि इस फिल्म की शूटिंग उनके लिए बहुत यादगार रही। लगभग 52 दिनों तक चली शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद 200 लोगों के साथ उनका गहरा रिश्ता बन गया। एक्ट्रेस ने लिखा, पहली बार का अनुभव हमेशा खास होता है। रिद्धिमा ने आगे लिखा, '52 दिनों तक 200 से ज्यादा लोग मिलकर इस मजेदार और खूबसूरत फिल्म को बनाने में लगे रहे। हमने साथ में योजना बनाई, डांस किया, हंसे, रोए और रोते-रोते हंसे। अब मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि यह फिल्म आप सबके सामने आए और आप भी इस जश्न में शामिल हों'  
 सेट पर दिखी कलाकारों की बॉन्डिंग... फिल्म के कलाकार विधान शर्मा ने भी शूटिंग के दिनों को याद करते हुए रिद्धिमा कपूर की तारीफ की। उन्होंने बताया कि सेट पर काम करने के साथ-साथ सभी ने खूब मस्ती की, दिमागी खेल खेले और एक-दूसरे के साथ बेहतरीन वक्त बिताया। कलाकारों के बीच की यही ट्यूनिंग अब फिल्म के ट्रेलर में भी साफ नजर आ रही है।

## 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

बड़ा ट्विस्ट, करण के अफेयर का शक गहराया, मचा हंगामा

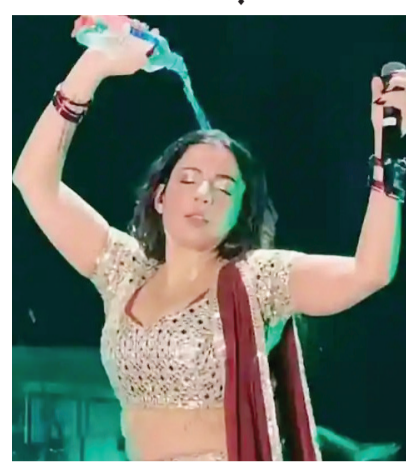


टीवी का आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इन दिनों अपने जबरदस्त ट्विस्ट और फैमिली ड्रामे से दर्शकों को बांधे हुए है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी है, जहाँ रिश्तों में झुंज राज धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। आने वाले एपिसोड में करण से जुड़ा एक बड़ा खुलासा होगा, जो न सिर्फ तुलसी बल्कि पूरे शान्तिनिकेतन परिवार को झकझोर कर रख देगा।  
 मुन्नी की खुशी के बीच नंदिनी को बेचनी... घर में मुन्नी की सफलता का जश्न मनाया जा रहा होता है, लेकिन नंदिनी का मन अशांत रहता है। तुलसी उससे बात कर उसे समझाने की कोशिश करती है कि करण को लेकर वह शायद गलत सोच रही है, लेकिन नंदिनी का शक कम होने के बजाय और गहरा जाता है।  
 करण से सीधे टकराएंगी नंदिनी... नंदिनी अपने शक को दबाने के बजाय करण का सामना करने का फैसला करती है। वह सबके सामने उससे अफेयर को लेकर तीखे सवाल करती है। घर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है और सभी हैरान रह जाते हैं।  
 बा की कसम पर भी नहीं थमेगा विवाद... स्थिति को संभालने के लिए तुलसी आगे आती है और करण

को बा की कसम देकर सच बताने के लिए कहती है। करण कसम खाकर खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन नंदिनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और विवाद और बढ़ जाता है।  
 परी के साथ होगा नया बवाल... कहानी में परी का ट्रेक भी नया मोड़ लेता है। अजय के घर पहुँचने पर एक गलतफहमी के कारण परी को अपमान झेलना पड़ता है। इस घटना से परिवार के रिश्तों में और खटास आ जाती है।  
 दूसरी औरत संग करण को देखेगा आर्यन... सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है, जब करण एक दूसरी औरत के साथ अस्पताल में नजर आता है। आर्यन उसे देख लेता है और उसकी तस्वीर खींचकर गौतम को भेज देता है, जिससे मामला और गंभीर हो जाता है।  
 तुलसी के सामने आएगी सच्चाई की तस्वीर... गौतम यह तस्वीर तुलसी को भेज देता है। जैसे ही तुलसी करण की दूसरी औरत के साथ फोटो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह है कि करण सच में निर्दोष है या कोई बड़ा राज छुपा रहा है - इसका खुलासा आने वाले एपिसोड्स में होगा।

## बॉलीवुड न्यूज

जैस्मीन सैंडलस का कॉन्सर्ट बना विवाद: पानी से खुद को भिगोया, लिप-सिंक देख भड़के फैंस



पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की 'गुलाबी क्वीन' कही जाने वाली और फिल्म 'धुरंधर' की मशहूर गायिका जैस्मीन सैंडलस एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। अहमदाबाद में आयोजित उनके हालिया कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसके बाद उनके लाइव प्रदर्शन की प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे हैं। अहमदाबाद के इस कॉन्सर्ट में जैस्मीन ने अपने सुपरहिट ट्रैक 'शरारत' पर परफॉर्म किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैस्मीन मंच पर बेहद ऊर्जावान नजर आ रही हैं और परफॉर्मिंग के बीच में ही उन्होंने नाटकीय अंदाज में अपने ऊपर पानी डाल लिया। हालाँकि, फैंस का ध्यान उनकी इस हरकत से ज्यादा उनके लिप-सिंक पर गया। ब्यासल क्लिप में साफ दिख रहा है कि जैस्मीन वास्तव में गा नहीं रही थीं, बल्कि पीछे चल रहे प्री-रिकॉर्डेड ट्रैक पर केवल हॉट हिला रही थीं। भारी भरकम टिकट खरीदने वाले फैंस को उम्मीद थी कि वे जैस्मीन को जादूई आवाज लाइव सुन पाएँगे, लेकिन 'लिप-सिंक' के तमाशे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

'रामायण' में रणवीर का लुक देख गदगद हुए अनुराग बसु



निदेशक नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' इन दिनों भारतीय सिनेमा ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणवीर कपूर के लुक को लेकर अब उनके पुराने सहयोगी और दिग्गज निदेशक अनुराग बसु ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उनके अभिनेता की तारीफ की। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की 'रामायण' सिनेमा जगत में चर्चा का एक अहम विषय बन गई है, खासकर इसके बड़े पैमाने और विज्ञान की वजह से। एक इंटरव्यू में, बसु - जिन्होंने पहले कपूर के साथ 'बर्फी' और 'जग्गा जासूस' जैसी फिल्मों में काम किया है - ने कहा कि एक्टर ने 'इस लुक को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है।' बसु ने टिप्पणी की कि जब रणवीर पहली बार इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, तो उनका लुक उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। उन्होंने भगवान राम जैसे किरदार को निभाने की चुनौती पर जोर दिया और इसे एक मुश्किल भूमिका बताया, जिसके लिए पक्के इरादे की जरूरत होती है।

जीनत अच्ची एक्ट्रेस नहीं थीं मुमताज ने किया तीखा तंज



बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच वैचारिक युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुँच गया है। बीते दौर को मशहूर अभिनेत्री मुमताज ने अपनी समकालीन कलाकार जीनत अमान के अभिनय कौशल और उनके 'स्टारडम' पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक हालिया एक इंटरव्यू में मुमताज ने दो टुक शब्दों में कहा कि वह जीनत को एक अच्छी अभिनेत्री नहीं मानतीं। एक बातचीत में, मुमताज ने जीनत अमान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह कोई बहुत अच्छी एक्टर नहीं थीं। मुमताज ने जीनत अमान को मिले अवॉर्ड्स की संख्या पर सवाल उठाया और टिप्पणी की, कि लालवानी के साथ हाल ही में हुई एक बातचीत में, मुमताज ने कहा, जीनत अमान बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं थीं, यह कहते हुए मुझे अफसोस है—मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगी। उन्हें कितने अवॉर्ड मिले? अगर आप हर किसी को स्टार कहेंगे, तो यह कैसे चलेगा? हर कोई स्टार नहीं होता। मुमताज ने स्टारडम की अवधारणा के बारे में अपने ट्विटर को विस्तार से बताया, यह संकेत देते हुए कि यह एक दुर्लभ उपलब्धि है जिसे हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स के कद तक नहीं पहुँच सकता और इस बात पर जोर दिया कि सच्चा स्टारडम एक ऐसा खिताब है जो केवल कुछ चुनिंदव लोगों को ही मिलता है।

## 6 दिन में बना डाला बड़ा रिकॉर्ड

कमाई में गिरावट के बीच भी 'भूत बंगला' का धमाका...

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में बनी हुई है। 17 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि गिरते कलेक्शन के बीच भी फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।  
 डे 6 का बॉक्स ऑफिस हाल... रिपोर्टरों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को करीब 6115 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। हालाँकि यह आंकड़ा पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 78190 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। वीकडेज में गिरावट

आना आम बात है, लेकिन फिल्म ने अपनी पकड़ पूरी तरह नहीं छोड़ी है।  
 तुलना और चर्चा में फिल्म... फिल्म की तुलना अन्य हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से भी की जा रही है। खासकर 'भूल भुलैया 3' से मुकाबले में यह थोड़ा पीछे नजर आई। वहीं, वामिका गब्बी की तुलना ऐश्वर्या राय बच्चन से किए जाने पर अक्षय कुमार ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि वामिका की अपनी अलग पहचान है और उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई है।  
 कुल मिलाकर, 'भूत बंगला' भले ही वीकडेज में थोड़ी धीमी पड़ी हो, लेकिन फिल्म की पकड़ अभी भी बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन में फिर उछाल देखने को मिल सकता है।



बना खास रिकॉर्ड... दिलचस्प बात यह है कि 'भूत बंगला' अब 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसमें आगे सिर्फ 'धुरंधर 2' और 'बाईर 2' जैसी बड़ी फिल्में हैं। इस उपलब्धि के साथ फिल्म ने अपनी मौजूदगी मजबूत तरीके से दर्ज कराई है।